ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

भारतीय ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना का प्रभाव : एक अध्ययन

रवि रस्तोगी
शोधार्थी,
छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय,
कल्यानपुर, कानपुर

राजीव शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग
डी0ए0वी0 कालेज,
सिविल लाइन, कानपुर

सारांश

आज भारत वर्ष में ग्रामीण युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को सुधारने के लिये प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना का प्रारम्भ किया है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण युवा वर्ग को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवा वर्ग को प्रशिक्षण देकर उन्हे रोजगार के अनुकूल तैयार करना है। एक अनुमान के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक अधिक से अधिक ग्रामीण युवा वर्ग को रोजगार प्रदान करना है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना है। जिससे भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन प्रदान कर सकता है और विश्व गुरू की संकल्पना को साकार कर सकता है।

मुख्य शब्द : एनएसडीसी, पीएमकेवीई, एसएससी, पीएमवाईवाई।

प्रस्तावना

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में विकराल होती बेरोजगारी की समस्या का दीर्घकालीन समाधान पेश करते हुये एक नई योजना का श्री गणेष 15 जुलाई 2015 को किया जिसे प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना का नाम दिया गया। सरकार ने इस योजना के तहत साल भर में 24 लाख युवाओं को सार्थक उद्योग, जगत के अनुकूल और कौशल आधारित प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा, जिससे ग्रामीण युवाओं को आत्म निर्भर एवं योजना के लाभ का मूल्यांकन हो सके प्रस्तुत शोध पत्र में इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों की भागीदारी तथा सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रो की विवेचना की गयी है तथा इस योजना के प्रमुख उद्देश्य जो कि ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर तथा स्वावलम्बी बनाना है जिसके फलस्वरूप वे अन्य लोगों को भी अपने रोजगार से जोड सकें, का भी अध्ययन किया गया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो सकेगी तथा बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकेगी।

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योकि भारत की आत्मा गावों में निवास करती है ग्रामीण युवा कृषि कार्यो पर अपना ध्यान अधिक लगाते है एवं ग्रामीण युवकों में शिक्षा का अभाव होता है। इसके लिये भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक कुशल भारत के निर्माण के लिये प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (स्किल इण्डिया मिशन) की शुरूआत की है इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमन्त्री ने 15 जुलाई 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जायेगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है, इसके द्वारा कौशल विकास के प्रयासों को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु नियोक्ताओं और नागरिको की आकाक्षाओं को ध्यान में रखते हुये बहुमुखी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत 31 जुलाई 2017 तक 31.22 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किये गये है जिनमें करीब 17 लाख पुरूष और 14 लाख महिलायें है।

इस योजना के प्रशिक्षण में 15 जुलाई 2017 से जीएसटी लेखा सहायक और योग प्रशिक्षण के चार रोजगार पाठ्यक्रम शामिल किये गये हैं और अभी 18 राज्यों में 85 जिलों के 91 प्रशिक्षण केन्द्रों ने जीएसटी लेखा सहायक पाठ्यक्रम शुरू किया है।

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (स्किल इण्डिया मिशन) कौशल भारत कुशल भारत की शुरूआत

भारत में दस साल कांग्रेस पार्टी के सत्ता के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ विजय प्राप्त की और इस जीत का श्रेय उस समय के गुजरात के मुख्यमन्त्री, वर्तमान में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को जाता है मोदी सरकार ने 2014 से ही सत्ता में आने के बाद से भारत के विकास के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये जैसे ''डिजिटल इण्डिया, मेक इन इंडिया आदि इन कार्यक्रमों के बाद मोदी सरकार ने ''कौशल विकास अभियान, स्किल इंडिया '' कार्यक्रम की शुरूआत की है यह एक बहुआयामी विकास योजना है इसके अन्तर्गत भारतीयों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जायेगी जिससे कि वो अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सके।

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिये अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रमों की शुरूआत है कौशल भारत – कुशल भारत की योजना भी इसी का एक भाग है। स्किल इण्डिया मिशन योजना के अन्तर्गत चार अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना) को सम्मिलित करके शुरू की गयी है।

एन0डी0ए0 सरकार द्वारा शुरू की गयी कौशल भारत–कुशल भारत योजना नयी योजना नही है इससे पहले यू0पी0ए0 सरकार ने भी स्किल डेवलपमेन्ट योजना को शुरू किया था उस समय यू0पी0ए0 सरकार ने वर्ष 2022 तक लगभग 500 मिलियन भारतीयों में कौशल विकास करने के लक्ष्य को रखा था। लेकिन एन0डी0ए0 सरकार द्वारा इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40 करोड कर दिया गया है। इस योजना में न केवल उद्यमी संस्थाओं को जोड़ा है बल्कि, पूरे भारत में कार्यरत सभी गैर सरकारी संस्थाओं से भी सम्बन्ध स्थापित किया है। इससे पहले ये योजना 20 मंत्रालयों द्वारा संचालित की जाती थी परन्तु अब मोदी सरकार ने इसे एक मंत्रालय द्वारा संचालित किया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित यह एक गैर लाभ अर्जक कम्पनी है यह देश में कौशल एवं शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का पहला उदाहरण है अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करने, समर्थन सेवाओं को सक्षम बनाने और आकार निर्माण करने में अहम भूमिका निर्वहन करने वाला यह निगम 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। अब यह एम0 एस0 डी0 ई0 (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय) का हिस्सा है और इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 15 करोड भारतीयों को कुशल बनाना है वर्ष 2016–17 में इसके कार्य निष्पादन से 34 राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के 540 जिले 2263 पाठ्याक्रमों के तहत 11 लाख अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया यह कौशल विकास के विस्तार हेतु देश भर में क्षेत्र कौशल परिषदो (एसएससी) की स्थापना कर रहा है अब तक 36 (एसएससी) स्थापित और 40 अनुमोदित हो चुके है, जो सरकार द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता क्षेत्रों तथा मेक इन इण्डिया के 25 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करती है।

शोध का उद्देश्य

शोध पत्र के अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. प्रधानमन्त्री की कौशल योजना का मूल्यांकन करना।
2. कौशल विकास के साथ उद्यमिता का मूल्यांकन करना।
3. बेरोजगार युवाओं पर कौशल विकास योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

शोध अध्ययन विधि

भारत मे युवाओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है यहॉ मानव संसाधनों के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिससे युवाओं में कौशल विकास योजना के बल पर विश्व स्तर पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को आत्म निर्भर बनाना है जिससे वह स्वालम्बी बन सके दुर्भाग्यवश कौशल विकास के मामले में हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले काफी पीछे है। सामाजिक शोध प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व एक निश्चित रूपरेखा का होना आवश्यक है ये रूप रेखा जो शोध के लिये मार्ग दर्षक का कार्य करती है जिसे शोध अभिकल्प कहते है प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेशणात्मक सह विवरणात्मक शोध के आधार पर बनाया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतो का प्रयोग किया गया है यह शोध पत्र द्वितीयक संमक पर आधारित है प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक संमक के लिये भारत सरकार की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, आदि से सम्बन्धित संमक लिये गये है। कौशल विकास योजना के प्रस्तुत आंकड़े विभिन्न रिपोर्ट से लिये गये है।

कौशल विकास योजना के उद्देश्य

देश में गरीबी का उन्मूलन कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार दिलाना इसके अलावा कौशल विकास योजना को अन्य उद्देश्य इस प्रकार है –

1. जो गरीब बच्चें शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं उनके अन्दर छुपे कौशल को जानना तथा इस योजना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा युवा शक्ति के हुनर को पहचान कर उन्हें उनके मुताबिक रोजगार दिलाना।
2. गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के अलावा गरीब परिवारों और युवा में स्किल डेवलपमेन्ट करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
3. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लोगों को ज्यादातर शिक्षा देना।

4. सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना चाहिये।
5. भारतीय बेरोजगार युवाओं को आत्म निर्भर रोजगार परक बनाकर राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करना।
6. ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को शिक्षित कराना एवं कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य कराना।

कौशल विकास योजना के लाभ

कौशल विकास योजना के प्रारम्भ होने से विभिन्न बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले है वह अपनी जीविका को चलाने के लिये स्वयं के रोजगार को शुरू कर सकते है तथा अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते है –

1. राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि।
2. कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत में बेरोजगारी की समस्या के निवारण में सहायता मिलेगी।
3. योजनाबद्व तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना।
4. देश के युवा जिस कौशल (जैसे गाड़ी चलाना, कपड़े सिलना, अच्छी तरह से खाना बनाना, साफ–सफाई करना, मकैनिक का काम करने बाल, काटना आदि) को परम्परागत रूप से जानते हैं उनके उस कौशल की गुणवत्ता को बढ़ाकर व प्रशिक्षित करके सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना है।
5. आने वाले दशको में पूरी दुनिया में कार्यकुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने के लिये विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उनके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र से ही कुशल बनाना।
6. भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या (जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है) की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये कौशल एवं अवसर प्रदान करना।
7. सभी राज्यों और संघ राज्यों को संगठित करके आई0आई0टी0 इकाइयों के माध्यम से दुनिया में स्वयं को स्थापित करना।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

देश में दक्ष एवं कुशल श्रम शक्ति की कमी को देखते हुये प्रधानमन्त्री ने 15 जुलाई 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस मिशन का उद्घाटन किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जायेगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है, इसके द्वारा कौशल विकास के प्रयासों को परिणामोंमुखी बनाने हेतु नियोक्ताओं और नागरिकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये बहुमुखी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत 20 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे है जिन्होनें वर्ष 2015–16 और 2016–17 के कौशलीकरण लक्ष्य क्रमशः 125.690 और 117.59 लाख की तुलना में क्रमषः 104.16 और 66.32 लाख अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

प्रधानमन्त्री युवा योजना (पीएमवाईवाई)–

प्रशिक्षुता शिक्षा प्रशिक्षण और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुॅच और सामाजिक उद्यमशीलता संवर्धन के लिये युवाओं के बीच उद्यम समर्थकारी परिस्थिति की सृजन के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री युवा उद्यमिता अभियान (युवा) योजना 9 नवम्बर 2016 को शुरू की गयी है। 30 साल तक के सभी भारतीय उद्यमियों के लिये उपलब्ध इस पंचवर्षीय (वर्ष 2016–17 से 2020–21) योजना का लक्ष्य 14.5 लाख युवाओं को शिक्षा, कौशल व उद्यमशीलता में प्रशिक्षित करना तथा कुल 260 सामाजिक उद्यम स्थापित करना है। साथ ही 30 हजार स्टार्टअप सृजित कर करीब 2.60 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा करना है इस योजना में 450 करोड रूपये व्यय किये जाने है और प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये 3050 संस्थान जिसमें उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान 300 स्कूल 500 आईटीआई ओर 50 उद्यमिता विकास केन्द्र में सिव ओपन आनलाइन कौर्सेज के माध्यम से शामिल किये जाने है।

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई)–

इस योजना की शुरूआत 9 जनवरी 2017 को 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रधानमन्त्री द्वारा की गयी। इसका उददश्य विदेशो में रोजगार और नौकरी की तलाष करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना है जिसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय मानको के साथ चुने हुये क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार मांग के अनुरूप युवाओं को प्रमाणित प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि भारतीय युवा जब व्यवसाय के लिये किसी नये देश जाये तो स्वयं को ठगा महससू न करे। इस योजना का नारा '' सुरक्षित जाये प्रशिक्षित जाये, विश्वास के साथ जाऐ '' यह योजना एमएसडीई के प्रशिक्षण भागीदारो और विदेश मंत्रालय के परामर्श एवं सहयोग से एनएसडीसी द्वारा चलाई जा रही है और इसके तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु अब तक देश के 9 राज्यों में 16 भारत अन्तर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किये गये है।

कृषि में कौशल विकास

देश के कृषि में धारित विविधता और उद्यम आधारित कौशल विकास हेतु व्यवसाय विशेष के लिये समर्पित संस्थान युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर रहे है। जैसे मधुमक्खी पालन में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, पिसीकल्चर, और मेरी कल्चर में केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी शोध संस्थान और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बार्ड एक्वाकल्चर में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, डेयरी में राष्ट्रीय डेयर विकास बोर्ड, रबर में रबड़ कौशल विकास परिषद और रबड़ बोर्ड, रेशम की पालन एवं व्यवसाय में समता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 4 विविध समशोध संस्थान, 64 शोध संस्थान, 15 राष्ट्रीय शोध केन्द्र और 13 परियोजना निदेशालय द्वारा समय पर कौशल विकास के पाठयक्रम संचालित किये जा रहे है।

महिलाओं में कौशल विकास

विभिन्न हितधारियों के सहयोग से सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देशभर में महिलाओं के लिये ई कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम– उज्जवल योजना, मिशन पूर्ण शक्ति, प्रियदर्शिनी योजना, सबल योजना, स्वाधार ग्रह योजना सक्षम योजना, ईडब्लयू आर प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टेप कार्यक्रम संचालित कर रहा है जिनसे बड़ी संख्या में महिलाये प्रशिक्षित हो रही है महिलाओं में कौशल विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अपनी योजनाओं के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके तहत वर्ष 2016–17 में 1.30 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है इसके लिये केन्द्रीय स्तर पर 16 क्षेत्रीय संस्थानों सहित नोएडा स्थित राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान दे रहे है। जिनकी वार्शिक समता में 32 पाठयक्रमों में 4436 महिलायें प्रशिक्षित करने की है तथा देश में 405 महिला आईटीआई और सामान्य आईटीआई में 1003 महिला खण्ड है जिनमें 67 इन्जीनियरी और 60 गैर इन्जीनियरी ट्रेडो में 83270 प्रशिक्षण सीटे हैं।

दिव्यागों में कौशल विकास योजना

जनगणना 2011 के अनुसार देश में 2.68 करोड दिव्यांग है जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है जिनके बहुमुखी विकास हेतु सरकार का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईडी) सक्रिय है और इसने एनएसडीसी के सहयोग से 2018 तक 5 लाख दिव्यांगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है इनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अलावा डीईडी के अधीन 7 राष्ट्रीय संस्थान भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे है जिनके द्वारा 2011 से अब तक करीब 20 हजार दिव्यागों को व्यावसायिक कौशल विकास दिया गया है 15–35 आयु के दिव्यागों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा दीनदायाल विकलांग पुनर्वास योजना चालाई जा रही है।

मुद्रा बैंक योजना

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने मुद्रा बैंक योजना की शुरूआत 8 अप्रैल 2015 को हुई है इस योजना को छोटे कारोबारियो को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम माना जा रहा है मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट फंड रिफाइनेंस एजेन्सी। इस बैंक के जरिये प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना मे 10 लाख रूपये तक के लोन दिये जायेगें मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई इस योजना के तहत तीन तरह के लोन मिल सकेगें। इनके नाम हैं शिशु, किशोर और तरूण। शिशु योजना के तहत 50 हजार रूपये तक के लोन मिल सकेगें। किशोर योजना के तहत 50 हजार रूपये से 5 लाख रूपये तक के लोन मिल सकेगें। तरूण योजना के तहत 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक के लोन दिये जायेगें।

मुद्रा बैंक से देश के छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सकेगा छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को इससे लोन मिलेगा इसके साथ ही सब्जी वालो, सैलून, खोमचे वालो को इस योजना का पूरा पूरा लाभ मिलेगा।

इस योजना के अन्तर्गत मुद्रा कार्ड प्रधानमंन्त्री लोन येाजना (डी0एम0एम0वाई) के अन्तर्गत जारी किया जायेगा यह डेविट कार्ड के जैसा एक कार्ड है जो मुद्रा लोन धारक को मुद्रा लोन के रूपये निकालने और भुगतान के लिये दिया जायेगा।

भारत सरकार इस योजना की सहायता से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये विशेष बजट तय किया है, इस बजट के अन्तर्गत महिलायें लोन पाकर अपना व्यापार कर सकेगी और स्वावलम्बी हो सकेगी इस बजट से लोन प्राप्त करके महिलायें सैलून, सिलाई, दुकान, हैंडी क्राफ्ट आदि का व्यापार कर सकेगी, ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत मुद्रा स्कीम होल्डर महिलाओं के लिये करीब 1.80 लाख करोड़ रूपया आबंटित किया जा चुका है।

कौशल विकास योजना की वर्तमान स्थिति

नीचे दी गयी तालिका के अनुसार सन 2014 से शुरू की गयी इस योजना के अन्तर्गत 1736 कौशल प्रबन्ध केन्द्रो की स्थापना की गयी तथा वर्ष 2017 में यह संख्या बढ़कर 8662 हो गयी जिसके अनुसार औसतन 3 वर्षो में 125 प्रतिशत की वृद्वि प्रशिक्षण केन्द्रो में हुई। इसी प्रकार वर्ष 2014 में इस प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या 1954300 थी जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 11725372 हो गयी, जिसके औसतन 600 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

एक अनुमान के अनुसार प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में 3 वर्षो में हुई वृद्वि यह दर्शाती है कि प्रधानमन्त्री के द्वारा चालू की गयी इस योजना का लाभ उठाने के लिये युवाओं में उत्साह है परन्तु यदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना में और गति प्रदान की जाये तो और युवा वर्ग इस योजना से लाभान्वित हो सकता है।

कौशल प्रबन्ध केन्द्र तथा प्रशिक्षित युवा वर्ग

क्र0 सं0	कौशल प्रबन्ध केन्द्रो की संख्या		केन्द्रो की प्रतिशत वृद्वि	एनएसडीसी पारिस्थितिकीय		(प्रशिक्षित युवा) वृद्वि प्रतिशत
1	2014 मई 1736	2017 मई 8662	499 प्रतिशत	2014 1954300	2017 11725372	600 प्रतिशत

स्रोतः कौशल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट – 2017

भारतीय ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना के प्रभाव

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिये अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया गया, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रम की शुरूआत रहा है, साथ ही साथ केन्द्र ने एक स्वतन्त्र मंत्रालय की स्थापना की है और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को कौशल विकास योजना के साथ जोड़ा गया है जिसमें खासकर ग्रामीण एवं गरीब युवा वर्ग का पूर्ण विकास हो सके।

इस योजना के माध्यम से देश में गरीबी का उन्मूलन करके ज्यादा से ज्यादा युवावर्ग को शिक्षित कर उन्हें रोजगार प्रदान किया जा रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौशल विकास 3.5 प्रतिशत है और 2019 तक भारत को 12 करोड़ कौशल युवाओं की जरूरत होगी। सरकार का लक्ष्य 2022 तक यह संख्या 40 करोड़ से भी ऊपर ले जाना है।

भारत में महिलाओं की सामान्य व्यथा है कि वो एक ही वातावरण एवं परिवेश में रहती है, उनके पास स्वयं का अधिकार नही होता एवं सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये भारत में नीति निर्माताओं ने महिलाओं के उत्थान को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत नीतिगत पहल की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शारीरिक श्रम आधारित कार्यो को कौशल आधारित बनाना है।

राष्ट्रीय स्तर पर भारत में दसवीं की पढ़ाई छोड़ने वालों का अनुपात 17.86 प्रतिशत है महिलाओं के संदर्भ में यह अनुपात 17.79 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण महिलाओं की कम आयु में विवाह, शिक्षा संस्थान, का घर से दूर होना तथा गरीबी है जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने स्किल इण्डिया मिशन की शुरूआत की जिससे सभी ग्रामीण युवावर्ग आत्म निर्भर हो सके।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, डिजिटल इण्डिया, प्रधानमन्त्री युवा योजना राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, तथा कौशल विकास योजना से बहुत से ग्रामीण युवा वर्ग लाभान्वित हुये है और इस योजना के द्वारा वह (युवा वर्ग) स्वयं का व्यवसाय कर रहे है। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दो में, ''कौशल विकास योजना केवल जेब में पैसे भरने जैसा नही है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्म विश्वास भरना है।'' यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आत्म निर्भर एवं शक्तिशाली विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना होगा यदि सरकार कुछ ऐसी रोजगार परक योजना को लाती है, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है।

सुझाव

1. कौशल विकास योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली परीक्षा, प्रमाण पत्रों एवं उनकी सम्बद्वता की गुणवत्ता में पारदर्शिता बनाये रखना आवश्यक है।
2. इस योजना के अन्तर्गत एजेन्सियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिये।
3. सरकार द्वारा अधिकृत संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये प्रशिक्षुओं की नकद पारितोशिक की राशि में वृद्वि की जानी चाहिये जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक अप्रशिक्षित युवा इस योजना के प्रति आकर्षित हो तथा योजना का लाभ उठा सके।
4. सरकार को ऐसे माध्यमों का निर्माण करना चाहिये जिसमें कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता हो।
5. राज्य सरकारों को अपने राज्य की भौगोलिक स्थित तथा वातावरण के अनुरूप ऐसी योजना बनाने का अधिकार होना चाहिये जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण युवा लाभान्वित हो सके।
6. सुदूर ग्रामीण अंचलों तथा क्षेत्रों में ऐसे कौशल प्रशिक्षण/शिक्षा केन्दों की स्थापना किये जाने की आवयकता है जिसमें आधुनिक संसाधन के माध्यम से शिक्षा दी जा सके।
7. सरकार को इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों के बहेतर शिक्षण और प्रशिक्षित की गुणवत्ता का समय–समय पर आकलन करना चाहिये, जिससे युवाओं का सही मार्ग दर्शन हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *दत्त, गौरव व महाजन अश्विनी : (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था एस चन्द एण्ड कम्पनी, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 275*
2. *मिश्र, एस0के0 व पुरी, वी0के0 : भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हापुड., मुम्बई।*
3. *आर्थिक समीक्षा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थक प्रमाण 2016–17*
4. *योजना पत्रिका 2017*
5. *कुरूक्षेत्र पंत्रिका 2017*
6. *बिजनेस स्टेण्डर्ड समाचार पत्र।*
7. *इकोनॉमिक्स टाइम्स समाचार पत्र।*
8. *www.upsdm.gov.in (गूगल)*